Amendment of Essential Commodities Aet

@1525. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether under the Essential Commodities Act, Sugar trade between whole sellers has been banned and if so, whether this would be allowed to ensure competitive distribution;

(b) whether jaggary, a perishable product, is proposed to be exempted from the provisions of the Act; and

(c) whether the Essential Commodities Act is proposed to be amended to remove lacunae?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI): (a) With a view to prevent hoarding and to ensure smooth flow of sugar to the consumers, only one sale transaction by a wholesaler to another wholesaler and that too, if accompanied by physical delivery of stocks, has ben permitted.

(h) and (c) No, Sir.

गेहूं का खरीद मूल्य

†1526. श्री भूपेन्द्र सिंह मान: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गेहूं का पिछला खरीद मूल्य क्या था और तब से लेकर कितनी मात्रा में गेहूं की खरी की गई ;

(ख) उपभोक्ताओं को गेहूं किस मूल्य पर बेचा गया ; और

(ग) इससे कुल कितना लाभ हुआ/हानि हुई ?

@Previously Unstarred question 093, transferred from the 28th November, 1991.

††पूर्वत: अतारांकित प्रश्न संख्या 697. 28 नवम्बर, 1991 से स्थानारित ।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) पहली अप्रैल, 1991 से प्रारंभ रबी विपणन मौसम, 1991-92 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 225 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था और 29-11-1991 तक 77.52 लाख मीटरी टन गेहूं वसूल कर लिया गया है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1-5-1990 से 234/- रुपए प्रति क्विंटल के एक समान केंद्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गौदामों से) पर गेहूं मुहैया किया जा रहा है । राज्यों संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनी वितरण लागत और मार्जिन, जो कि राज्य पूर्ति राज्य भिन्न-भिन्न होते हैं, को जोड़ने के बाद स्वयं निश्चित खुदरा मूल्य निर्धारित किए जाते हैं ।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं के लाभ के लिए गेहूं का केंद्रीय निर्गम मूल्य भारतीय खाद्य निगम की वसूली लागत से कम रखा जाता है और इस वजह से दी जाने वाली राज सहायता को सरकार द्वारा वहन किया जाता है । यद्यपि कुल राशि वर्ष में जारी की जाने वाली गेहूं की मात्रा पर निर्भर करेगी, लेकिन वर्ष 1991-92 (बजट अनुमान) के लिए सरकार द्वारा इस समय गेहूं के लिए 98.39 रुपए प्रति क्विंटल की राज सहायता वहन की जा रही है ।

Warehousing Capaciiy

1527. SHRI JAGADISH JANI; Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the existing Warehousing capacity available in the country is inadequate;